

अडानी, अंबानी ग्रुप की मीडिया कंपनियाँ भी नए प्राइवेसी कानून के विरोध में उतरीं

मीडिया संस्थानों का कहना है कि नए कानून के कारण पत्रकार को किसी व्यक्ति के खिलाफ जानकारी एकत्रित करने से पहले उससे अनुमति लेनी होगी

-नेपू मि्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 26 अक्टूबर। अरबपति उद्योगपतियों मुकेश अंबानी और गौतम अडानी के स्वामित्व वाली कंपनियों सहित, 21 समाचार प्रकाशकों के एक समूह ने भारत के निजता कानून को अदालत में चुनौती दी है। उनका कहना है कि यह कानून खोजी पत्रकारिता को बाधित करेगा और केन्द्र सरकार को पत्रकारों के सूत्रों की पहचान करने का अवसर देगा। अदालती दस्तावेजों से यह जानकारी सामने आई है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार ने पिछले साल व्यक्तिगत डिजिटल डेटा की सुरक्षा के लिए निजता कानून लागू करने की घोषणा की थी। इससे मेटा और गूगल जैसे डिजिटल मंचों पर नियमों के अनुपालन की जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। समाचार प्रकाशकों का कहना है कि मीडिया संस्थानों को कानून से छूट नहीं दिए जाने के कारण यह प्रेस की स्वतंत्रता

- नया कानून व्यक्ति को अधिकार देता है कि वह पत्रकार को जानकारी जुटाने के लिए दी गई अनुमति कभी भी वापस ले सकता है और एकत्रित जानकारी नष्ट करने की मांग कर सकता है।
- अनुमति की शर्त से पत्रकारों को खबरों का “सोर्स” उजागर करने के लिए मजबूर होना पड़ जाएगा, जो कि पत्रकारिता के सिद्धांत के खिलाफ है।
- मीडिया संस्थानों ने इस कानून के खिलाफ 6 अक्टूबर को अदालत में चुनौती दी थी, इस पर मंगलवार को सुनवाई होगी।

में हस्तक्षेप करता है।

भारत के डिजिटल न्यूज़ पब्लिशर्स एसोसिएशन (डीएनपीए) ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एक गोपनीय याचिका में कहा है कि अगस्त में सरकार के साथ हुई बैठक के दौरान, मीडिया कंपनियों को आश्वासन दिया गया था कि कानून प्रेस की स्वतंत्रता को रक्षा करेगा। लेकिन यूरोपीय संघ, सिंगापुर और ब्रिटेन की

तरह पत्रकारों के लिए कानून में लिखित छूट का प्रावधान नहीं होना चिंताजनक है। याचिका 6 अक्टूबर को दायर की गई, लेकिन इसकी खबर पहली बार अब सामने आई है। इस पर मंगलवार को सुनवाई होगी है। इसे मोदी सरकार के निजता कानून के खिलाफ अब तक की सबसे चर्चित कानूनी चुनौती माना जा

रहा है। इससे पहले केवल अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए काम करने वाले कार्यकर्ताओं और कुछ छोटे समाचार संस्थानों ने इस कानून को चुनौती दी थी। यह अंबानी और अडानी के नेतृत्व वाले कारोबारी समूहों की ओर से सरकार को दी गई एक असामान्य चुनौती भी है। विपक्षी दल आरोप लगाते रहे हैं कि ये उद्योगपति मोदी के करीबी हैं और उन्हें सरकार से अनुकूल व्यवहार मिलता है। हालांकि, संबंधित कारोबारी समूहों और सरकार ने विपक्ष के इन आरोपों को जोरदार ढंग से खारिज किया है।

डीएनपीए और संबंधित मीडिया समूहों ने टिप्पणी के अनुरोधों का जवाब नहीं दिया। भारत के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। समाचार प्रकाशक मांग कर रहे हैं कि कानून के उन अधिकांश विवादास्पद प्रावधानों को रद्द किया जाए, जो मई 2027 से लागू होने हैं। उनका तर्क है (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

‘हम 30 सैकेण्ड में प्रोटैस्ट रद्द कर सकते हैं’

‘अगर प्रधानमंत्री ज्ञानेश कुमार को सीईसी पद से हटा देते हैं तो’

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 26 अक्टूबर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को दिल्ली के व्यापारियों से कहा कि वे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की अपील करें। उन्होंने कहा कि यदि सरकार यह मांग मान लेती है, तो मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन 30 सेकंड में बंद हो जाएंगे।

राहुल गांधी ने सोशल मीडिया मंच “एक्स” पर एक पोस्ट में आरोप लगाया कि एसआईआई के खिलाफ प्रदर्शनों के दौरान मेट्रो सेवाएं बंद करके, सड़कों को सील करके और प्रतिबंध लगाकर सरकार राजधानी में कारोबार को बाधित कर रही है।

‘घटिया देश है नॉर्वे, वहां के लोगों को अमेरिका नहीं आने देना चाहिए’

वाशिंगटन, 26 अक्टूबर। अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिलने पर नॉर्वे के प्रति अपना गुस्सा फिर जाहिर किया है। उन्होंने नॉर्वे को घटिया देश करार दिया और कहा कि वह इस देश

- नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिलने पर फिर भड़के ट्रंप।

के लोगों को अमेरिका में आने नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि वहां की राजधानी ओस्लो स्थित नोबेल समिति ने उन्हें शांति पुरस्कार नहीं दिया। ट्रंप ने रविवार को मिशिगन के पोर्ट ब्लुम में एक रैली के दौरान यह बात कही। वह देश में अगले सप्ताह होने वाले मध्यावधि चुनाव के प्रचार में जुटे हुए हैं। उन्होंने कहा कि वह कुछ देशों के लोगों का स्वागत करेंगे, लेकिन नॉर्वे के लोगों का नहीं। ट्रंप ने कहा, क्योंकि मुझे नोबेल पुरस्कार नहीं मिला। इसलिए मैं नॉर्वे के (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

लूला डा सिल्वा चौथी बार ब्राजील के राष्ट्रपति निर्वाचित

ब्रासीलिया (ब्राजील), 26 अक्टूबर। देश के वर्तमान राष्ट्रपति लुइज इनसियो लूला डा सिल्वा ने एक बार फिर चुनाव जीत लिया है। वह चौथी बार ब्राजील के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। वामपंथी नेता 80 वर्षीय सिल्वा पूर्व

- रविवार को एक कड़े मुकाबले (रन-ऑफ) में उन्होंने फ्लावियो बोल्सोनारो को हरा दिया।

फैक्टर की कर्मचारी हैं। चुनाव के पहले दौर में राष्ट्रपति पद के दावेदार और अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के करीबी फ्लेवियो बोल्सोनारो और मौजूदा राष्ट्रपति लूला के बीच बराबरी रही। रविवार को एक कड़े मुकाबले (रन-ऑफ) में उन्होंने फ्लावियो बोल्सोनारो को हरा दिया।

लूला डा सिल्वा ब्राजील के इतिहास में सबसे लंबे समय तक (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

मोदी पर खड़गे की टिप्पणी पर भड़की भाजपा, देश भर में प्रदर्शन

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 26 अक्टूबर। भाजपा ने सोमवार को सभी राज्यों में पार्टी मुख्यालयों पर प्रदर्शन किया और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से इस्तीफा देने की मांग की। भाजपा ने कहा कि खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बारे में अशोभनीय और अपमानजनक टिप्पणी की है।

यह विवाद रविवार को शुरू हुआ और बाद में बढ़ गया। पटना में एक कार्यक्रम के दौरान खड़गे ने एक श्रोता की टिप्पणी के जवाब में कहा, “मोदी का बाबा भी जाएगा।” उस व्यक्ति ने कहा था कि “प्रधानमंत्री कहीं नहीं जाएंगे।” भाजपा के कई नेताओं ने इस टिप्पणी को लेकर खड़गे की कड़ी आलोचना की। वहीं, कांग्रेस ने सवाल उठाया कि जब सोनिया गांधी और खुद खड़गे के लिए पहले अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया था, तब भाजपा ने ऐसा विरोध क्यों नहीं किया था।

बिहार में बड़ी संख्या में भाजपा

भाजपा ने कहा, प्र.मंत्री के स्व. पिता पर टिप्पणी के लिए खड़गे को माफी मांगनी चाहिए

- भाजपा ने देश भर में खड़गे के खिलाफ भारी प्रदर्शन किया, उनके पुतले जलाए।
- कांग्रेस ने खड़गे के बचाव में भाजपा पर सवाल उठाया कि जब भाजपा खड़गे व सोनिया गांधी के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करती है, तब भाजपा नेताओं ने ऐसा विरोध क्यों नहीं किया।

नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मार्च निकाला। उन्होंने खड़गे के खिलाफ नारे लगाए और उनके इस्तीफे की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने कांग्रेस अध्यक्ष का पुतला भी जलाया। जम्मू में भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने खड़गे के पोस्टर जलाए और नारे लगाए। बैंगलुरु के “फ्रीडम पार्क” में भाजपा ने खड़गे से माफी की मांग को लेकर बड़ा प्रदर्शन किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खड़गे की टिप्पणी की निंदा करते हुए कहा कि

रक्षा मंत्री ने कहा, “कांग्रेस यहीं नहीं रुकी। खड़गे जी के शब्दों को सही ढंग से उठारने की कोशिश करके, वह लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचा रही है। अपनी गलती स्वीकार करने और खेद जताने के बजाय, कांग्रेस इस बयान का बचाव करने और उसे सही साबित करने में लगी हुई है।”

केन्द्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने खड़गे पर निशाना साधने के साथ-साथ कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर भी तंज किया। उन्होंने कहा कि भाजपा राहुल गांधी की अपरिपक्वता के बारे में पहले से जानती थी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि गलत संगति में रहने के कारण पार्टी के दूसरे नेता भी इससे संक्रमित हो गए हैं। जोशी ने कहा, “उनकी पार्टी में हर कोई अपरिपक्व, निराश और हताश हो गया है। इतने निचले स्तर पर उतरकर, (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

रक्षा मंत्री ने कहा, “कांग्रेस यहीं नहीं रुकी। खड़गे जी के शब्दों को सही ढंग से उठारने की कोशिश करके, वह लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचा रही है। अपनी गलती स्वीकार करने और खेद जताने के बजाय, कांग्रेस इस बयान का बचाव करने और उसे सही साबित करने में लगी हुई है।”

केन्द्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने खड़गे पर निशाना साधने के साथ-साथ कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर भी तंज किया। उन्होंने कहा कि भाजपा राहुल गांधी की अपरिपक्वता के बारे में पहले से जानती थी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि गलत संगति में रहने के कारण पार्टी के दूसरे नेता भी इससे संक्रमित हो गए हैं। जोशी ने कहा, “उनकी पार्टी में हर कोई अपरिपक्व, निराश और हताश हो गया है। इतने निचले स्तर पर उतरकर, (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

आसियान रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन के लिए राजनाथ सिंह फिलीपींस जाएंगे

नई दिल्ली, 26 अक्टूबर। फिलीपींस के सेबू में 28 से 29 अक्टूबर तक होने वाली 13वीं एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस (आसियान) डिफेंस मिनिस्टर्स

- दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र संघ (आसियान) का गठन 2010 में हुआ था।

मोंटिंग (एडीएमएम) –प्लस में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। वे क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दों पर फोरम को संबोधित करेंगे। रक्षा मंत्री एडीएमएम-प्लस के दौरान हिस्सा लेने वाले देशों के अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे आसियान देशों के साथ चल (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

महत्वपूर्ण हो सकती है। प्रधानमंत्री पद के लिए नागपुर से जुड़े और आरएसएस के करीबी माने जाने वाले दो नेताओं के नाम चर्चा में हैं-केन्द्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस।

हालांकि, इन सभी नामों को फिलहाल अटकलों के रूप में ही देखा जाना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने अभी तक अपने पते नहीं खोले हैं कि क्या वे अगले साल अपना उत्तराधिकारी चुनेंगे। अगले साल सात राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने हैं और भाजपा के प्रदर्शन को देखते हुए आगे का फैसला किए जाने की संभावना जताई जा रही है।

यदि मोदी स्वयं भारत का राष्ट्रपति बनने का फैसला करते हैं, तो सवाल उठेगा कि प्रधानमंत्री पद पर उनकी जगह कौन लेगा। उनके करीबी सहयोगी और केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह अब उनकी पसंदीदा पसंद नहीं रह गए हैं। इसकी वजह युवा पीढ़ी के

खिलाफ उठाए गए उनके कदम बताए जा रहे हैं। मोदी का इस नई पीढ़ी पर काफी भरोसा था, लेकिन आरोप है कि शाह के कदमों से उनका समर्थन कमजोर हुआ है। इस स्थिति में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की भूमिका भी